

संपादक की कलम से

कैसा हो जन हितकारी बजट

-भरत झुनझुनवाला-

बजट में बुनियादी संरचना जैसे हाइवे, बदरगाह इत्यादि में सरकारी निवेश बढ़ने की पूरी संभावना है। यह सही भी है। लेकिन बुनियादी संरचना दोनों प्रकार की होती है द्व्युपक बड़ी और दूसरी छोटी। बड़ी बुनियादी संरचना से बड़े उद्योगों को लाभ अधिक होता है जैसे हाइवे बनने से सूरत से कोलकाता माल पहुंचाना आसान हो जाता है। लेकिन इसी बड़ी संरचना से कोलकाता के छोटे उद्यमियों का धंधा पिटता है। जैसे यदि सूरत का सस्ता कपड़ा कोलकाता आसानी से पहुंचे तो कोलकाता के बुनकरों का धंधा पिटता है। इसलिए जरूरी है कि बड़ी संरचना के साथ-साथ छोटे आम आदमी के लिए लाभप्रद संरचना जैसे छोटे कस्तों में मुफ्त वाईफाई, गांव में सड़क, गांव में सीवेज का निस्तारण, बिजली की व्यवस्था इत्यादि में पर्याप्त निवेश किया जाए। ऐसा निवेश करने से गांव के लोगों को अपना माल सस्ता बनाने में सहृदयत होगी और वे बड़े उद्यमियों के सामने खड़े होकर अपना माल बेच सकेंगे और अपना जीवनयापन कर सकेंगे। इसलिए मात्र बुनियादी संरचना में निवेश बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। उसकी दिशा आम आदमी के लिए उपयोगी बुनियादी संरचना की तरफ मोड़ना जरूरी है। बजट में सरकारी इकाइयों के निजीकरण की प्रक्रिया तेज करने के आसार हैं। जैसे एयर इंडिया का हाल में निजीकरण किया गया और कुछ बैंकों के भी निजीकरण की चर्चा हो रही है। अभी तक की व्यवस्था थी कि घाटे में चल रही सार्वजनिक इकाइयों मात्र का निजीकरण किया जाता है। यह विचारधारा ठीक नहीं है क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक कोई सरकारी इकाई लाभ कमाती है, तब तक उसे सरकारी धेरों में रखा जाएगा और जब वह घाटे में चली जाए तब ही उसका निजीकरण किया जाए। यह उसी प्रकार हुआ जब तक फल सड़ न जाए तब तक उसकी बिक्री न करें। इसके स्थान पर सरकार को घाटे में चल रही इकाइयों के निजीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि वे घाटे में जाए अथवा फल सड़ उससे पहले ही उसकी बिक्री हो जाए जिससे कि सरकार को पर्याप्त धन मिल सके।

राष्ट्रीय उत्सव के नए आयाम

-डॉ. दिलीप अग्निहोत्री-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मादो राष्ट्रीय पर्वों पर औपचारिकता के निवाह तक सीमित नहीं रहते। राष्ट्रीय चेतना से जनमानस को जोड़ते हैं। देश के सुदूर क्षेत्रों तक इस भावना का विस्तार करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का एक हफ्ते तक विस्तार किया गया। इसमें राष्ट्र नायकों के स्मरण के अवसर समाहित किया गए। इसके पहले नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया था। इसे अनेक स्तरों के समारोहों से सजाया गया। राष्ट्रीय राजधानी से लेकर गांवों व जनजातीय इलाकों तक इसका प्रकाश पहुंचाया गया। इसमें राष्ट्रभाव के अनेक उपेक्षित प्रसंग उजागर हुए। इसके पहले नरेंद्र मोदी पद्म सम्मानों को भी सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा चुके थे। देश में गुमनामी में रहते हुए भी

-योगेश कुमार गोयल

संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाने वाला 'वार्षिक वित्तीय विवरण' केन्द्र सरकार का बजट कहलाता है, जो देश के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है। 'बजट' एक पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'पर्स'। भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर बजट एक निश्चित अवधि के लिए पूर्वनिर्धारित राजस्व और व्यय का अनुमान होता है, जो भविष्य की वित्तीय स्थितियों को दर्शाता है और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है। भारतीय सर्वधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष का केन्द्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। केन्द्रीय बजट को राजस्व बजट तथा पूँजीगत बजट में वगीर्कृत किया जा सकता है। बजट के जरिये सरकार आर्थिक नीतियों को लागू करती है और हर साल पेश किए जाने वाले बजट का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। इस दस्तावेज में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय पर विस्तृत टिप्पणियां दी

An image showing a hand placing a gold coin on top of a stack of coins, symbolizing budgeting or financial management. The word "Budget" is overlaid in large red letters across the center. The background is filled with blurred banknotes, suggesting money or wealth.

जाती हैं। बजट में शामिल प्रस्ताव संसद को स्वीकृति मिल जाने के बाद 1 अप्रैल से लागू हो जाते हैं, जो अगले साल 31 मार्च तक लागू रहते हैं। बजट निर्माण की पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की ही होती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तमंत्री निर्माला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को बजट पेश किया गया। यह लगातार चौथा ऐसा अवसर है, जब उन्होंने देश का आम बजट पेश किया है। वैसे यह जानना दिलचस्प है कि आगामी वित्त वर्ष के लिए जो केन्द्रीय बजट कुछ धंतों में पेश कर दिया जाता है, उसकी तैयारी करीब पांच माह पहले ही शुरू हो जाती है। इन तैयारियों के दौरान वित्त मंत्रालय केन्द्र सरकार के अमंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों साथ मीटिंग करता है, जिसके आधार पर वह तब किया जाता है कि किस मंत्रालय अथवा विभाग को वित्त वर्ष के लिए कितने रकम दी जाए। इन मीटिंग्स में तब होने वाले एक ब्लॉप्रिंट तैयार किया जाता है जो बजट का प्रारूप तैयार हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री एक बैठक मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मिलकर बजट का अवलोकन करते हैं और वित्त तथा राजस्व संबंधी नीतियों को निश्चित करते हैं। सम्पूर्ण मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत होने के बाद केन्द्रीय बजट संसद में प्रस्तुत कि-

जाता है। भारत में वित्त वर्ष प्रतिवर्ष एक अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है और बजट के विवरण में इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का ब्यारा शामिल होता है। सरल शब्दों में कहें तो बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजना होती है, जिसके जरिये यह तय करने का प्रयास किया जाता है कि सरकार अपने राजस्व की तुलना में खर्च को किस हद तक बढ़ा सकती है। यह कावायद इसीलिए होती है क्योंकि सरकार को अपने राजकोषीय घाटे का एक लक्ष्य हासिल करना होता है। बजट आमतौर पर तीन प्रकार का होता है- संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। संतुलित बजट में आय और खर्च की मात्रा का समान होना जरूरी है जबकि अधिशेष बजट में सरकार की आय खर्चों से अधिक होती है और घाटे के बजट में सरकार के खर्च उसकी आय के स्रोतों से अधिक होते हैं। सरकारी बजट तीन प्रकार के होते हैं, परिचालन या चालू बजट, पूँजी या निवेश बजट और नकदी या नकदी प्रवाह बजट। सरकार की आय के प्रमुख साधनों में विभिन्न प्रकार के कर और राजस्व, सरकारी शुल्क, जुमार्ना, लाभाश, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि तरीके शामिल होते हैं बजट से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं पर नजर डालना भी काफी दिलचस्प है। पहले बजट की कुछ प्रतियां छपती थी लेकिन अब बजट पूरी तरह डिजिटल हो गया है। 2016 तक फरवरी माह के अंतिम दिन आम बजट पेश किया जाता था किन्तु 2017 में तकालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। 1999 तक बजट भाषण फरवरी के अंतिम कार्यदिवस पर शाम पांच बजे पेश किया जाता था लेकिन 1999 में यशवंत सिन्धा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। 2017 से पहले रेल बजट भी अलग से पेश किया जाता था लेकिन 2017 में उसे आम बजट में ही समाहित कर दिया गया। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही पेश किया जाता था लेकिन उसके बाद इसे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश करना शुरू कर दिया गया। 1950 तक बजट का मुद्रण राष्ट्रपति भवन में होता था किन्तु इसके लीक होने के बाद इसका मुद्रण दिल्ली की मिंटो रोड स्थित प्रेस में होने लगा और 1980 से वित्त मंत्रालय के अंदर सरकारी प्रेस में ही इसका मुद्रण होता है। 1947 से लेकर अब तक देश में 73 आम बजट, 14 अंतर्रिम बजट व 4 विशेष या मिनी बजट पेश किए जा चुके हैं। वैसे भारत में बजट पेश करने का सिलसिला 162 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब 7 अप्रैल 1860 को इंस्ट इंडिया कम्पनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री व नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश समाजी के समक्ष पहली बार भारत का बजट रखा था।

भाजपा को दिया अपनों ने झटका

पार्टी विद डिफरेंस की

पाठ्य नियंत्रण का लाइन कर राजनीति में खुद को अन्य सभी पार्टीयों से अलग व श्रेष्ठ बताने वाली भारतीय जनपार्टी (भाजपा) इन दिनों अपनों द्वारा दिए रखे झटकों से उबर नहीं पा रही है। देश पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पांचों प्रदेशों चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा रही है। इसी दौरान विभिन्न पार्टीयों ने नेताओं द्वारा दलबदल का खेल भी जोरों से चल रहा है। इस दौरान सबसे अधिक झटक भाजपा को लगा है। कुछ वर्षों पूर्व सत्ता लालच में भाजपा में शामिल होकर सत्ता सुख भोगने वाले नेता ऐन चुनाव के बाहिर छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो जाने का लगे हैं। भाजपा के बढ़ते जनाधार को देखकर दूसरे दलों के बहुत से ऐसे मौकापरस्त हो जिनकी अपने दलों में दाल नहीं गल रही वो सभी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा भी दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को भय उपकृत किया। उन्हें विधानसभा व लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया तथा चुनाव जीतने उनको मंत्री भी बनाया। ऐसे में दलबदल पार्टी में आने वाले नेताओं के क्षेत्रों में वर्षों भाजपा के लिए काम करने वाले पार्टी



खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। दल-बदलू नेताओं को भाजपा में पूरी तरजीह मिली। इसका फायदा उठाकर उन्होंने जहां अर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त की, वही पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने समर्थकों को विभिन्न पदों पर बैठाया। इससे पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में निराशा व्याप्त होने के कारण वह धीरे-धीरे मुख्यधारा से किनारे हो गए। लंबे समय तक सत्ता का दोहन करने के कारण अन्य दलों से भाजपा में आये बहुत से नेताओं पर भ्रष्टाचार के अरोप लगने लगे। उनके नाम के साथ कई तरह के विवाद जुड़ गए। ऐसे में चुनाव नजदीक आने पर जब उन्हें पार्टी में फिर से टिकट नहीं मिलने का अंदेशा हो गया तो उन्होंने अपने पद पर रहते ही भाजपा विरोधी किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए। इससे एक तो चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ने से जहां भाजपा की हवा खराब हुई। वहां, पार्टी के समने एकाएक मजबूत प्रत्याशी खड़ा करना मुश्किल हो गया। दूसरे दलों से भाजपा में आए कई नेताओं ने तो पद पर रहते ही भाजपा को अलविदा कह कर पार्टी की किरकिरी भी कराई। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में आए नाना पटोले ने भाजपा टिकट पर प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज नेता को पराजित किया था।

चुनावी घोषणाओं से भरा बजट

-सिद्धार्थ शंकर-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए बजट में किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। बजट में सभी तबके के लोगों का ध्यान रखने की कोशिश की गई। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इसमें किसानों को डिजिटल सेवा देना, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाना शामिल है। इसके अलावा पांच नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, सिंचाई-पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि, 12 करोड़ से अधिक किसानों की उमीदों को झटका लगा है। पीएम किसान के 12 करोड़ से अधिक किसानों को उमीद थी कि इस बार बजट में पीएम किसान की राशि कम से कम डेढ़ गयी हो जाएगी, पर ऐसी नहीं

हा सका। नौकरी-पेशा करने वाले लोगों को भी मायूसी हाथ लगी है। सीतारमण ने बजट 2022 में इनकम टैक्स को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की। इससे इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और इनकम टैक्स रेट्स घटाए जाने की उम्मीद लगाए हुए आम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। वित्त मंत्री बजट में वर्क फ्रॉम होम डिडक्षन या स्टैंडर्ड डिडक्षन लिमिट में बढ़ोत्तरी से जुड़ी कोई भी घोषणा नहीं की और न ही स्टैंडर्ड डिडक्षन की लिमिट में कोई बदलाव किया गया है। बावजूद इसके बाजार ने बजट का दिल खोलकर स्वागत किया। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। बजट भाषण के दौरान बैंकिंग स्टॉक में जबरदस्त तेजी रही। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स करीब 750 अंक मजबूत होकर 58,780 अंक के पार कारोबार कर रहा था। बजट पर सरकार ने किसानों पर खास जो दिया है। किसान आंदोलन नुकसान से निपटने सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। किसानों को डिजिटल सेवा देने, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने, देशभर में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर दूरी दायरे में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के ऐलान किए गए हैं। साल 2023 के सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। पिछले वर्ष मोटे अनाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बात की थी। अब बजट में ऐलान किया गया है कि सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर वर्ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 44 हजार 605 करोड़ रुपए का लागत से केन-बेतवा लिंबंग परियोजना को शुरू करने का ऐलान किया है।

चुनौती बनती जा रही बढ़ती आर्थिक असमानता

-योगेश कुमार गोयल-

पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित विश्व आर्थिक मच के द्वावों पेश गैर सरकारी संगठन 'ऑक्सफैम' की रिपोर्ट 'इनडिकलिटी किल्स' के अनुसार कोरोना महामारी के दौर में अमीर जहां और अमीर होते जा रहे हैं, वहाँ गरीब और गरीब हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान भारत के अरबपतियों की कुल सम्पत्ति बढ़कर दोगुने से अधिक हो गई और इस दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या भी 39 फीसदी बढ़कर 142 हो गई है। देश के दस सर्वाधिक अमीर लोगों के पास इतनी सम्पत्ति है, जिससे पूरे ढाई दशकों तक देश के बच्चे को स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दी जा सकती है। आर्थिक असम्भानता पर आवाहन इस रिपोर्ट के मुताबिक 142 भारतीय अरबपतियों के पास कुल 719 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति है और देश के सबसे अमीर 98 लोगों की कुल सम्पत्ति भारत के

55.5 करोड़ सबसे गरीब लोगों की कुल सम्पत्ति के बराबर है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महामारी के दौरान सबसे धनी 10 फीसदी लोगों ने राष्ट्रीय सम्पत्ति का 45 फीसदी हिस्सा हासिल किया, जबकि निचले स्तर की 50 फीसदी आवादीमें के हिस्से मात्र छह फीसदी राशि ही आई रिपोर्ट में सरकार से राजस्व सृजन के प्राथमिक स्रोतों पर पुनर्विचार करने तथा कर्म प्रणाली के अधिक प्रगतिशील तरीकों को अपनाने का आग्रह करते हुए सुझाव दिया गया है कि इन अरबपतियों पर वार्षिक सम्पत्ति कर लगाने से प्रतिवर्ष 78.3 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जिससे सरकारी स्वास्थ्य बजटमें 271 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है कोरोना महामारी के इस दौर में एक ओर जहां करोड़ों लोगों के काम-धन्धे चौपट हो गए, लाखों लोगों की नौकरियां छूट गईं, अनेक लोगों के कारोबार घाटे में चल गए, वहाँ कुछ ऐसे व्यवसायी हैं, जिन्हें इस महामारी ने पहले से कई गुना ज्यादा मालामाल कर दिया है आंकड़े देखें तो भारत में मार्च 2020 से

नवम्बर 2021 के बीच देश के 84 फीसदी परिवारों की कमाई में कमी आई और 4.6% करोड़ लोग तो अत्यंत गरीबी में चले गए। इस बीच जितने लोग पूरी दुनिया में गरीबी वे दलदल में फंसे, भारत में यह संख्या उसकी आधी है। एक ओर जहां गरीबों की संख्या बढ़ी तेजी से बढ़ी है, वहीं भारत में अब इतने अरबपति हो गए हैं, जितने फ्रांस, स्वीडन तथा स्विट्जरलैण्ड को मिलाकर भी नहीं हैं। अति धनादय वर्ग तथा अत्यंत गरीबी में फंसे लोगों के बीच की चौड़ी होती खाई अन्दर कमज़ेर वर्गों को भी प्रभावित कर रही है और आर्थिक विषमता चिंताजनक स्थिति तक बढ़ गई है और विश्व बैंक पहले ही चेतावनी देते चुका है कि दस करोड़ से ज्यादा लोग चरम गरीबी में धकेले जा सकते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में घिछले साल भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि यदि कोरोना के कुबेरों से वर्षालू होती तो भुखमरी नहीं फैलती। विश्व के कई अन्य देशों के साथ भारत में भी बढ़ती आर्थिक असमानता काफी चिंताजनक है और बढ़ती विषमता का दृष्टिभाव देश के

विकास और समाज पर दिखाई देता है और इससे कई तरह की सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियां भी पैदा होती हैं। करीब दो साल पहले भी यह तथ्य सामने आया था कि भारत के केवल एक फीसदी सर्वाधिक अमीर लोगों के पास ही देश की कम आय वाली सत्तर फीसदी आबादी की तुलना में चार गुना से ज्यादा और देश के अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी ज्यादा सम्पत्ति है। आज विश्व आर्थिक पत्रिका 'फोर्ब्स' की अरबपतियों की सूची में सौ से भी ज्यादा भारतीय हैं जबकि तीन दशक पहले तक इस सूची में एक भी भारतीय नाम नहीं होता था। हालांकि देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए लेकिन गर्व भी तो तभी हो सकता है, जब इसी अनुपात में गरीबों की आर्थिक सेहत में भी सुधार हो। बहरहाल, ॲक्स्प्रेसफैम की रिपोर्ट में मांग की गई है कि धनी लोगों पर उच्च सम्पत्ति कर लगाते हुए श्रमिकों के लिए मजबूत संरक्षण का प्रबंध किया जाए।

